मोदी-आबे की बुलट दोस्ती

आतंक के मसले पर चीन-पाक को दो टूक हिदायत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और मील का पत्थर स्थापित करते हुए जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारत को बुलेट ट्रेन की सौगात देकर इसकी बुनियाद रख दी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क की कमान संभालने के बाद से पीएम मोदी की जिन वैश्विक नेताओं से गहरी और प्रगाढ़ मित्रता कायम हुई है उनमें आबे का नाम शीर्ष पर है। शायद यही वह कारण है जिस वजह से भारत और जापान का रिश्ता बड़ी तेजी से एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है। मोदी और आबे की इन मुलाकातों में दोनों देशों के बीच जारी बहुस्तरीय सहयोग की समीक्षा के साथ ही भविष्य में इसे और बढ़ाने पर जो भरोसा कायम हुआ उसकी झलक मोदी-आबे के बयानों से साफ देखी जा सकती है। दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात में परमाणु ऊर्जा, रक्षा उपकरणों की खरीद-फरोख्त और भारत के बुनियादी ढांचे के सुधार में जापान के सहयोग का मुद्दा छाया रहा। पिछले कुछ समय में भारत-जापान मैत्री आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर प्रगाढ़ हुई है। डोकलाम सीमा पर भारत और चीन के बीच चली तनातनी के दौरान भारत, जापान और अमेरिका ने साथ मिलकर सैन्य अभ्यास किया। जुलाई में भारत-जापान असैन्य परमाणु समझौता भी लागू हो गया, जिसके तहत जापान भारत में छह नए एटमी ऊर्जा संयंत्र लगाएगा। पिछले डेढ़ दशकों में भारत के विकास में जापानी निवेश ने अहम भूमिका निभाई है। जापान की मदद से देश में कई परियोजनाएं चल रही हैं और कई प्रस्तावित हैं। भारत और जापान 'एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजेसी)' पर काफी जोर-शोर से काम कर रहे हैं। आबे और मोदी की मुलाकात से इस प्रॉजेक्ट को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इस वृहद परियोजना में ईरान के चाहबहार बंदरगाह को विकसित करना भी शामिल है, जिसके जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक भारत की पहुंच आसान हो जाएगी। यह एक तरह से चीन के 'वन बेल्ट वन रोड' प्रॉजेक्ट का जवाब भी होगा। एशिया में चीन की बढ़ती आक्रामकता को ध्यान में रखते हुए जापान और भारत, दोनों को अभी एक दूसरे की जरूरत है। जहां तक बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट का प्रश्न है तो इसका मकसद अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए यात्रियों को तेज यात्रा का एक विकल्प उपलब्ध कराना और देश की इकोनॉमी को रफ्तार देना है। लेकिन इसे लेकर एक तरफ देश में उत्साह है तो दूसरी तरफ कई सवाल भी हैं। कहा जा रहा है कि जापान द्वारा इसके लिए बहुत आसान शर्तों पर और बहुत कम ब्याज पर कर्ज दिया जा रहा है। लेकिन यह कर्ज डॉलर में दिया जाएगा, तो डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट का रुझान देखते हुए कहीं हम अपने ऊपर कर्ज का बहुत ज्यादा बोझ तो नहीं लेने जा रहे हैं! एक आशंका यह भी है कि खर्च की एक अलग मद सामने आ जाने के कारण कहीं संकटग्रस्त भारतीय रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं और न बढ़ जाएं! लोग चाहते हैं कि बुलेट ट्रेन तो आए, लेकिन मौजूदा रेलवे ढांचे में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्राथमिकता में कोई ढील न आने पाए। सरकार को इन आशंकाओं का निराकरण करना चाहिए। लेकिन दोनों प्रमुख नेताओं की महत्वपूर्ण मुलाकातों के बाद जिस तरह चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है उससे ड्रैगन की खीझ समझी जा सकती है। आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दे पर जिस तरह से शिंजो आबे ने भारत की चिंता का समर्थन करते हुए चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी है उसने इन दोनों देशों की धड़कनें बढ़ा दी है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत उसी का हिस्सा है।

> **दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क की कमान संभालने के बाद से पीएम मोदी की जिन वैश्विक नेताओं से गहरी और प्रगाढ़ मित्रता कायम हुई है उनमें आबे का नाम शीर्ष पर है। शायद यही वह कारण है जिस वजह से भारत और जापान का रिश्ता बड़ी तेजी से एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है। मोदी और आबे की इन मुलाकातों में दोनों देशों के बीच जारी बहुस्तरीय सहयोग की समीक्षा के साथ ही भविष्य में इसे और बढ़ाने पर जो भरोसा कायम हुआ उसकी झलक मोदी-आबे के बयानों से साफ देखी जा सकती है।**

तबाही और महाविनाश का भीषणतम मंजर नजर आएगा चहुंओर

अगर युद्ध हुआ तो कितना खतरनाक होगा उत्तर कोरिया!

उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध लगना जारी है तो दूसरी तरफ उसका मिसाइल परीक्षण भी थम नहीं रहा है। हर एक प्रतिबंध के बाद उत्तर कोरिया और आक्रामक होकर सामने आता है। शुक्रवार तड़के उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल जापान की तरफ दागी। जापानी पीएम शिंजो आबे भारत के दौरे पर हैं ऐसे समय उत्तर कोरिया ने यह कदम उठाया है। कोरियाई प्रायद्वीप पहले भी युद्ध झेल चुका है। 1950 में उत्तर कोरिया के मौजूदा सुप्रीम नेता किम जोंग उन के दादाजी किम इल सुंग ने दक्षिण कोरिया पर हमला करने का फैसला लिया था। अमेरिका ने मामले में मध्यस्थता करने की कोशिश की ताकि युद्ध को रोका जा सके। तनाव तीन साल तक जारी रहा और इससे जन-धन दोनों का ही भारी नुकसान हुआ।

छह दशक बाद आज इस प्रायद्वीप में फिर से एक अलग तरह का तनाव देखने को मिल रहा है। अपने परमाणु परीक्षणों से किम जोंग उन अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चुनौती दे रहे हैं।

इस महीने की शुरुआत में उत्तर कोरिया ने सफल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया और दावा किया कि ये मिसाइलें अलास्का तक हमला कर सकती हैं। इसके तुरंत बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस बारे में बयान जारी कर इस परीक्षण की कड़ी निंदा की और कहा, इस मिसाइल का परीक्षण करने से अमेरिका, हमारे सहयोगियों, इस क्षेत्र और सारी दुनिया के लिए खतरा और बढ़ गया है।

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगले तीन सालों के भीतर उत्तर कोरिया ऐसे मिसाइल बना लेगा जो लॉस एंजिल्स शहर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि तनाव जारी रहा तो उत्तर कोरिया के साथ एक बड़े संघर्ष की संभावना है। 1950 में कोरिया का युद्ध शुरू हुआ। उस वक्त विश्व की महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व के कई देशों की तरह अपने पुनर्गठन में लगे थे। प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से पर सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया था जबकि अमेरिका दक्षिणी हिस्से पर सैन्य मदद दे रहा था। जून 25 को सोवियत संघ और चीन से समर्थन ले कर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर धावा बोल दिया। अमेरिका ने कम्युनिस्टों के हमले का सामना करने के लिए दक्षिण कोरिया में अपनी सेनाएं भेजीं।

अमेरिका की मदद से दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल को दो महीनों के भीतर आजाद भी करवा लिया गया। लेकिन प्रायद्वीप को एक करने के लिए अमेरिका की अपनी सेनाओं को उत्तर की तरफ भेजने के फैसले का चीन ने कड़ा विरोध किया। सभी पक्ष एटम बमों और परमाणु बमों की बातें करने लगे। जल्दी ही कोरिया प्रायद्वीप को एक करने के लिए शुरू की गई मुहिम तीसरे (परमाणु) विश्व युद्ध बनने की कगार पर पहुंच गई।

कोरियाई प्रायद्वीप में हुए पहले युद्ध में 30 लाख लोगों की मौत हुई थी और करीब एक लाख बच्चे अनाथ हो गए थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए में कोरियाई मामलों की जानकार सू टेरी बताती हैं, लाखों कोरियाई नागरिक मारे गए, करीब एक लाख बच्चे अनाथ हुए, एक करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा।

वो कहती हैं, प्योंगयांग पूरी तरह तबाह हो चुका था। एक भी इमारत नहीं बची थी जो आपको सही सलामत दिख जाए। 27 जुलाई 1953 को दोनों पक्षों ने अस्थाई तौर युद्धविराम पर हस्ताक्षर करने का फैसला लिया। लेकिन कहा जाए तो आज 64 साल बाद भी दोनों देश युद्ध जैसे माहौल में उलझे हुए हैं। इस इलाके में शत्रुता बढ़ रही है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बीच तनाव बढ़ रहा है। इस पर कुछ जानकारों का मानना है कि हल्की-सी चूक हुई तो फिर से युद्ध शुरू हो सकता है।

यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जटाउन में सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज में विश्लेषक और अमेरिकी सेना के कर्नल रहे डेविड मैक्सवेल का कहना है, दोनों देशों के बीच मौजूद विसैन्यीकृत (डीमिलिटराइज्ड) इलाका आज विश्व का सबसे अधिक हथियारों से भरा इलाका है। वो कहते हैं, उत्तर कोरिया की सेना में 11 लाख कर्मचारी हैं और इनमें से 70 फीसदी राजधानी और इस डीमिलिटराइज्ड इलाके के बीच तैनात हैं।

जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया के पास 60 लाख सैनिकों की सेना है जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। डेविड कहते हैं, मुझे लगता है कि ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। डेविड मानते हैं कि उत्तर कोरिया के हाल में किए परमाणु परीक्षण और मिसाइल लांच से अमेरिका पर हमले की संभावना बढ़ गई है। अगर किम जोंग-उन हमला करना चाहें तो उत्तर कोरिया के कमांडर आग बरसाने के आदेश दे सकते हैं और दक्षिण कोरिया में भारी तबाही ला सकते हैं।

जानकारों के अनुसार, पहले कुछ घंटों में सैंकड़ों हजारों मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं जो सियोल को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर सकती हैं। कुछ मिनटों में मिसाइलें उत्तर कोरिया से सियोल पहुंच जाएंगी। यहां ढाई करोड़ लोग रहते हैं और इतने लोगों को बचा कर सुरक्षित स्थान पर ले जाना संभव नहीं होगा।

डेविड कहते हैं, अनुमानों की मानें तो युद्ध के पहले ही दिन 64 हजार तक मौतें हो सकती हैं। जिस तरह की हानि होगी उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

साल 1950 की तरह उत्तर कोरिया चाहेगा कि वो अपनी सेनाओं को दक्षिण की तरफ भेज कर दक्षिण कोरिया के साथ समझैता करे और कोरियाई प्रायद्वीप को एक करके अपने नियंत्रण में रखे। उस वक्त उत्तर कोरिया नहीं चाहता था कि इस मामले में अमेरिका दक्षिण कोरिया की मदद के लिए आए। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और अमेरिका तुरंत सियोल की मदद के लिए मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। अमेरिका का टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। हाल में दक्षिण कोरिया में दोनों देशों की सेनाओं ने साझा युद्धाभ्यास किया था। एंजेलो स्टेट यूनिवर्सिटी में डिपार्टमंट ऑफ स्टडीज सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस में प्रोफेसर ब्रूस बेच्टोल कहते हैं, अमेरिका दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया के कब्जे में कभी नहीं जाने देगा।

पेंटागन में उत्तर पूर्व एशिया मामलों के जानकार बेच्टोल कहते हैं, युद्ध हुआ तो पहले हफ्ते में हमारे पायलटों के लिए काफी काम होगा। हमारी पहली कोशिश होगी कि हवाई ताकत का पूरा इस्तेमाल उत्तर कोरिया को आगे बढ़ने से रोकने में करें और हम भारी हथियारों की खेप के पहुंचने का इंतजार करें। जैसे-जैसे इलाके में अमेरिकी सैन्य सहायता बढ़नी शुरू होगी हमारे लड़ाकू विमान उत्तर कोरिया पर बमबारी करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे उत्तर कोरिया अमेरिका सेना के दवाब में आएगा चीजें बदतर हो सकती हैं और ये युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है।

बेच्टोल कहते हैं, जब किम जोंग उन और उनके 5000 करीबी सहयोगियों को इस बात का अहसास होगा कि उनके पास देश छोड़ कर जाने का वक्त नहीं हैं तो उनके पास परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल करने और हजारों-लाखों अमेरिकियों को ना मारने की कोई वजह नहीं रहेगी।

> **जापानी पीएम शिंजो आबे भारत के दौरे पर हैं ऐसे समय उत्तर कोरिया ने यह कदम उठाया है। कोरियाई प्रायद्वीप पहले भी युद्ध झेल चुका है। 1950 में उत्तर कोरिया के मौजूदा सुप्रीम नेता किम जोंग उन के दादाजी किम इल सुंग ने दक्षिण कोरिया पर हमला करने का फैसला लिया था। अमेरिका ने मामले में मध्यस्थता करने की कोशिश की ताकि युद्ध को रोका जा सके। तनाव तीन साल तक जारी रहा और इससे जन-धन दोनों का ही भारी नुकसान हुआ। छह दशक बाद आज इस प्रायद्वीप में फिर से एक अलग तरह का तनाव देखने को मिल रहा है। अपने परमाणु परीक्षणों से किम जोंग उन अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चुनौती दे रहे हैं।**